



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3411]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 2018/भाद्र 9, 1940

No. 3411]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 2018/BHADRA 9, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

**का.आ. 4220(अ).**—केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में **खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल भिन्न-भिन्न प्रकार के हाईड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिनके अंतर्गत सिंथेटिक ईंधन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और उसी प्रकार के ईंधन और तेल भी हैं, के विनिर्माण या उत्पादन में** लगी उद्योग सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 26 में आती हैं, को **लोक उपयोगिता सेवाएं** हो, जैसा कि उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 781(अ), तारीख 23 फरवरी, 2018 द्वारा तारीख 1 मार्च, 2018 से छह मास की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए **तारीख 1 सितम्बर, 2018 से छह मास की अवधि के लिए** लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2018-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2018

**S.O. 4220(E).**—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the services in industry **engaged in Manufacture or production of mineral oil (crude oil), motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, lubricating oils and the like;** which is covered by item 26 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a **public utility service** for the purpose of the said Act, as was notified for a period of six months with effect from the 1<sup>st</sup> March, 2018 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O.781(E), dated the 23<sup>rd</sup> February, 2018;

And whereas, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, **for a further period of six months with effect from the 1<sup>st</sup> September, 2018.**

[F. No. S.11017/2 /2018-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.